राज कुमार सोनी और अन्य

बनाम

उत्तरप्रदेश राज्य और अन्य

अप्रैल 3,2007

(पी.के. बालासुब्रमण्यम और बी. सुदर्शन रेड्डी, जे. जे.)

यू. पी. जमींदारी उन्मूलन और भूमि राजस्व अधिनियम-धारा 122 (6) आवासीय उद्देश्यों के लिए सरकारी भूमि का आवंटन-अनियमित भूमि को रद्द करना - आबंटन उप-मंडल अधिकारी एक को भूमि आबंटन और उसके बाद खरीदार के नाम पर भूमि के हस्तांतरण का निर्देश-जिला मजिस्ट्रेट ने खरीदार के पक्ष में हस्तांतरण आदेश को रद्द कर दिया-

जिसे उच्च न्यायालय ने सही ठहराया - उप-मंडल अधिकारी के पास सरकारी भूमि आवंटित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है-शक्ति केवल जिला मजिस्ट्रेट के पास निहित है-उप-मंडल अधिकारी द्वारा आदेश खरीदार के पक्ष में कानून के अनुसार नहीं होने के कारण, जिला मजिस्ट्रेट ने इसे रद्द करने में न्यायसंगत ठहराया-

इस प्रकार, उच्च न्यायालय के आदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं करने का आह्वान किया गया है-हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप एक अवैध और शून्य आदेश का पुनरुत्थान होगा।

उप-मंडल अधिकारी ने तीस साल की अवधि के लिए एम के पक्ष में सरकारी भूमि आवंटित की। एम ने एक स्वीकृत योजना प्राप्त की और निर्माण कार्य सुनिश्चित किया। अपीलकर्ताओं ने एम. से निर्माण को खरीदा और फिर उनके पक्ष में भूमि के परिवर्तन की मांग की। उप-कलेक्टर ने भूमि राजस्व के भुगतान पर अपीलार्थियों के नाम पर भूमि के हस्तांतरण का निर्देश दिया। जिला मजिस्ट्रेट ने अपीलार्थियों को कारण दर्शाओ नोटिस जारी किया कि उप-मंडल अधिकारी द्वारा उनके पक्ष में की गई भूमि के अनुदान को क्यों रद्द नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उप-मंडल अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट में आवासीय उद्देश्य के लिए सरकारी भूमि देने के अधिकार के रूप में भूमि देने के लिए अधिकृत नहीं है और इसके बाद उप-मंडल अधिकारी द्वारा अपीलार्थियों के पक्ष में किए गए हस्तांतरण आदेश को रद्द कर दिया। अपीलकर्ताओं ने जिले द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी मजिस्ट्रेट/कलेक्टर। उच्च न्यायालय ने उप-मंडल अधिकारी का आदेश सुनाया।

एम को भूमि आबंटित करना और उसके बाद अपीलार्थियों के नाम पर भूमि के हस्तांतरण को शून्य और अधिकार क्षेत्र के बिना निर्देशित करना। इसलिए वर्तमान अपीलें प्रस्तुत हुई।

अपीलार्थियों ने तर्क दिया कि जिला मजिस्ट्रेट के निष्कर्षों में कहा गया है कि भूमि के आवंटन के मामले में उप-मंडल अधिकारी की शक्ति वापस ले ली गई है जो पूरी तरह से आधारहीन है; कि उत्पादन का अभाव है उसकी कार्यवाही की एक प्रति; कि कारण दर्शाओ नोटिस में कोई नहीं था।

उप-मंडल को प्रदत्त शक्ति की वापसी का उल्लेख करें अधिकारी और इस प्रकार, उप-मंडल अधिकारी का आदेश नहीं हो सकता था अलग रखें; और यह कि आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। प्रत्यर्थी-राज्य ने तर्क दिया कि कार्यवाही सही से पट्टा विलेख के निष्पादन तक भूमि का आवंटन शुरू से ही शून्य है; कि उप-मंडल अधिकारी एम के पक्ष में सरकारी भूमि आवंटित करने के लिए अधिकृत नहीं था और उसके बाद उसे अपीलार्थियों के पक्ष में स्थानांतरित कर दिया गया और इस तरह उच्च न्यायालय ने उनके द्वारा पारित आदेशों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने अभिनिर्धारित किया-

1.1 उच्च न्यायालय ने स्पष्ट और स्पष्ट शब्दों में पाया कि उप-मंडल अधिकारी के पास सरकारी भूमि देने/आवंटित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था और शक्ति केवल जिला कलेक्टर के पास निहित थी। अपीलार्थी ने अभिवचन नहीं किया और न्यायालय की संतुष्टि के लिए यह स्थापित नहीं किया कि उप-मंडल अधिकारी को इच्छुक पक्षों द्वारा आवेदन के बल पर सरकारी भूमि आवंटित करने/अनुदान देने का अधिकार क्षेत्र प्रदान किया जाता है। यह कानून का एक मौलिक सिद्धांत है कि एक व्यक्ति असाधारण का आह्वान करता है भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र स्वच्छ हाथों के साथ आना चाहिए और इसका पूरा और पूर्ण खुलासा करना चाहिए।

न्यायालय को तथ्य। पक्षकारों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए अपने तथ्यों को चुनने का अधिकार नहीं है। मूलभूत तथ्यों को स्वीकार करने की आवश्यकता है।

न्यायालय को प्राधिकरण द्वारा कथित रूप से उल्लंघन किए गए अधिकार की प्रकृति और सामग्री की जांच करने में सक्षम बनाना। [पैरा 11] [739-एफ-एच; 740-ए]

1.2 . नियम के एक सादे अध्ययन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि परगनाधिकारी केवल राज्यपाल की ओर से पट्टा विलेख पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत। नियम कहीं भी परगनाधिकारी को किसी भी व्यक्ति

के पक्ष में पट्टे पर सरकारी भूमि आवंटित करने की शक्ति प्रदान नहीं करते हैं। [पैरा 14] [740-ई-एफ]

1.3 . उप-मंडल अधिकारी ने इसके पक्ष में भूमि आवंटित नहीं की अपीलकर्ताओं ने एम. के पक्ष में दिए गए अनुदान को रद्द करने के बाद यह पाए जाने पर कि एम ने अनुदान के नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया है, उप-मंडल अधिकारी ने पट्टा अनुदान को रद्द कर दिया और 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। 2000/- एम पर और साथ ही अपीलार्थियों के पक्ष में भूमि का हस्तांतरण किया। यह मानते हुए कि उप-मंडल अधिकारी के पास अधिकार और अधिकार क्षेत्र था। गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए भूमि का पट्टा देने के लिए, अधिक से अधिक योग्यता के आधार पर अपीलकर्ताओं के आवेदन पर विचार किया जा सकता था ताकि यह तय किया जा सके कि क्या वे कोई सरकारी भूमि देने के हकदार हैं, लेकिन किसी भी परिस्थिति में उप-मंडल अधिकारी आदेश पारित नहीं कर सकते थे अपीलार्थियों के नाम पर भूमि का हस्तांतरण। [पैरा 15] [740-एफ-एच; 741-ए)

1.4 . यह जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी कारण दर्शाओ नोटिस में सच है। सरकारी भूमि के पट्टा अनुदान के अनुसार उप-मंडल अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों को वापस लेने के आदेश का कोई उल्लेख नहीं है। हालांकि, यह कहा गया है कि परगनाधिकारी/उप-मंडल अधिकारी सरकारी अनुदान

अधिनियम के तहत भूमि देने के लिए अधिकृत नहीं है, आवासीय उद्देश्यों के लिए कुछ हद तक भूमि देने का अधिकार जिला मजिस्ट्रेट के पास निहित है।

यह जिला मजिस्ट्रेट के अंतिम आदेश में उन कार्यवाहियों के बारे में उल्लेख किया गया है जिनके तहत उप-मंडल अधिकारी को अनुदान देने से बहुत पहले उप-मंडल मजिस्ट्रेट की शक्तियों को वापस ले लिया गया था। अपीलार्थी तकनीकी रूप से यह तर्क देने में सही हो सकते हैं कि जिला कलेक्टर का आदेश उन आधारों पर आधारित है जिनका अपीलार्थी को जारी कारण दर्शाओ नोटिस में विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया था। [पैरा 16] [741-बी-सी]

1.5 . अपीलार्थी यह स्थापित करने में विफल रहे कि उन्होंने कानूनी रूप से सुरक्षा प्रदान की हैभूमि का आवंटन। अपीलार्थियों पर यह अभिवेदन करना और यह स्थापित करना कर्तव्य है कि उप-मंडल अधिकारी द्वारा उनके पूर्ववर्ती के पक्ष में आवंटन/अनुदान के आदेश ने कोई कानूनी अधिकार पैदा किया है और यह भी स्थापित किया है कि उनके पक्ष में भूमि का हस्तांतरण उप-मंडल अधिकारी द्वारा किया गया है। उच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि उप-मंडल अधिकारी का आदेश जिस पर उप-मंडल अधिकारी का पूरा दावा है -

अपीलार्थियों का विश्राम अमान्य और अनुचित था। उच्च न्यायालय स्वयं इस तरह के अमान्य और अनुचित आदेश को रद्द कर सकता था। इसलिए इस तर्क पर कुछ भी नहीं होता है। भले ही प्राकृतिक न्याय के नियमों का कोई तकनीकी उल्लंघन हुआ हो, यह हस्तक्षेप के लिए उपयुक्त मामला नहीं है, इस तरह के हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप एक अवैध, अमान्य आदेश का पुनरुत्थान होगा। इस मामले को ध्यान में रखते हुए इस मामले में न्याय किया गया है और उच्च न्यायालय ने इसे फिर से शुरू करने से इनकार कर दिया है

या उप-मंडल अधिकारी के आदेश को पुनर्जीवित करें जो कानून में अप्रवर्तनीय है। [पारस 12 और 16] [740-बी; 741-ई-एफ]वेंकटेश्वर राव बनाम ए. पी. सरकार, ए. आई. आर. (1966) एस. सी. 828 और एम. सी. मेहता बनाम। भारत संघ, ए. आई. आर. (1999) एस. सी. 2583 का उल्लेख किया गया है।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः 2007 की सिविल अपील सं. 1763

इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के सिविल विविध मामले 1999 की रिट याचिका संख्या 20708 में अंतिम निर्णयों और दिनांकित 01.09.1999 और 08.04.2005 आदेशों से।

अपीलार्थी की ओर से सुधीर चंद्र, जसबिर सिंह मलिक और एस. के. सभरवाल, अवतार सिंह रावत।

एएजी, उत्तरांचल राज्य और जतिंदर कुमार भाटिया उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

बी. सुदर्शन रेड्डी, जे.

1. अनुमति दी गई।

2. 31-3-1993 पर उप-मंडल अधिकारी, कोटद्वार ने मंजूरी दे दी। पौड़ी गढ़वाल जिला (उत्तरांचल) के गांव झोंक में स्थित खसरा No.1003 में विचाराधीन भूमि को महंथ गोविंद दास नामक व्यक्ति को आवंटित करना। उसी दिन, उप-मंडल अधिकारी पट्टा विलेख के निष्पादन की तारीख से तीस साल की अवधि के लिए आबंटित व्यक्ति के पक्ष में पट्टा विलेख निष्पादित करता है। कहा जाता है कि उक्त महंथ गोविंद दास ने विकास प्राधिकरण, हरिद्वार से कुछ निर्माणों को खड़ा करने के लिए एक स्वीकृत योजना के लिए आवेदन किया और प्राप्त किया।

इसमें अपीलकर्ताओं ने उक्त महंथ गोविंद दास से दिनांक 26-4 1995 के पंजीकृत बिक्री विलेख के तहत उठाए गए/मालवा के निर्माण खरीदे। अपीलार्थी दावा करते हैं कि उन्होंने भूमि भी खरीदी है, जैसा कि रिट

याचिका में उनकी दलीलों और दलीलों से स्पष्ट होता है। यह ध्यान देने योग्य है कि यह भूमि सरकार की है।

3. अपीलकर्ताओं ने अपने आवेदन दिनांक 15-5-1995 द्वारा कलेक्टर से अपने पक्ष में परिवर्तन करने का अनुरोध किया, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने महांत गोविंद दास से भूमि नहीं, बल्कि मलबा खरीदा है। द. उप-कलेक्टर ने अपीलार्थियों द्वारा इस प्रकार प्रस्तुत आवेदन पर विचार करने के बाद पाया कि "अनुदान धारक महांत गोविंद दास ने आवासीय भवन और दुकानों के मलबे को कब्जे के साथ बेच दिया। 2-5-1995 पर आवेदकों के पक्ष में पंजीकृत बिक्री विलेख। यदि अनुदान के उल्लंघन के कारण मलबा हटाया जाता है, तो अनावश्यक मुकदमेबाजी शुरू होने की संभावना है और यदि पक्का घरों को हटा दिया जाता है, तो कई कानूनी बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे राज्य सरकार को लाभ नहीं होता है। इसलिए उन्हें भूमि से बेदखल करना उचित नहीं लगता है। हालाँकि, डिप्टी कलेक्टर ने राज कुमार सोनी बनाम के स्थानांतरण का निर्देश देने वाले आवेदन का निपटारा कर दिया।

भूमि राजस्व के भुगतान पर अपीलकर्ताओं के नाम पर स्वयं भूमि का 157.50 पैसे भुगतान करना।

4. कोटद्वार गढ़वाल के जिला मजिस्ट्रेट ने कारणदर्शक नोटिस जारी किया है।आई. डी. 1 पर जारी किए गए आदेश में अपीलकर्ताओं से यह

बताने की आवश्यकता थी कि उप-मंडल अधिकारी, कोटद्वार द्वारा उनके पक्ष में दी गई भूमि के अनुदान को रद्द क्यों नहीं किया जाना चाहिए। कारण दर्शाओ नोटिस में, यह आरोप लगाया गया है कि उप-मंडल अधिकारी ने अपीलार्थियों के पक्ष में अनधिकृत रूप से भूमि प्रदान/आवंटित की है। यह विशेष रूप से आरोप लगाया जाता है कि उप-मंडल अधिकारी भूमि देने के लिए अधिकृत नहीं है, क्योंकि आवासीय उद्देश्य के लिए सरकारी भूमि देने का अधिकार जिला मजिस्ट्रेट के पास निहित है! अपीलार्थियों ने अपना विस्तृत स्पष्टीकरण उक्त कारण दर्शा कर प्रस्तुत किया।

नोटिस, अन्य बातों के साथ-साथ, यह तर्क देते हुए कि प्राधिकरण ने कानूनी जांच के बाद ही अनुदान दिया है और उन्होंने भूमि पर मौजूदा भवन के नवीनीकरण में काफी राशि खर्च की है और इसमें कुछ नए निर्माण भी किए हैं।

जिनके संबंध में किसी भी समय कोई आपत्ति नहीं उठाई गई है। यह तर्क दिया गया कि उनके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही कानूनी रूप से बनाए रखने योग्य नहीं है। यह भी तर्क दिया गया कि उन्होंने कार्यकाल धारकों का दर्जा हासिल कर लिया है। जिला मजिस्ट्रेट ने अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद स्पष्ट रूप से पाया कि उप-मंडल अधिकारी के पास वर्ष 1993 में महांत गोविंद दास को भूमि आवंटित करने का कोई अधिकार नहीं था। कलेक्टर तद्नुसार अभिनिर्धारित किया

गया कि उप-मंडल अधिकारी द्वारा निष्पादित आवंटन और पट्टा के आदेश ने भूमि में कोई अधिकार, स्वामित्व और ब्याज महांत गोविंद दास के पक्ष में प्रदान नहीं किया।

महंथ गोविंद दास ने उक्त भूमि को बिना किसी कानूनी अधिकार के अपीलार्थियों को बेच दिया। जिला मजिस्ट्रेट/ कलेक्टर ने यह भी पाया कि उप-मंडल अधिकारी ने अपने अधिकार का दुरुपयोग कियामहंथ गोविंद दास को भूमि का अनुदान शुरू होने से लेकर अपीलार्थियों को भूमि के हस्तांतरण तक हर चरण में। उप-मंडल अधिकारी द्वारा अपीलार्थियों के पक्ष में किए गए हस्तांतरण के आदेश को तदनुसार रद्द कर दिया गया है और राजस्व अभिलेखों में भूमि के मालिक के रूप में सरकार के नाम को विधिवत शामिल करने के लिए उचित निर्देश जारी किए गए हैं।

5. अपीलकर्ताओं ने जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर द्वारा पारित आदेश को सिविल विविध रिट याचिका संख्या 20708/ 1999 में दिनांकित 10-5-1999 में चुनौती दी।

यह तर्क देने की मांग की गई कि जैसे कि अपीलकर्ताओं ने महांत गोविंद दास से ही जमीन खरीदी है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने रिट याचिका की सुनवाई के दौरान इसे छोड़ दिया है। यह दावा किया गया था कि देने की शक्ति पट्टा सहायक कलेक्टर में निहित है, जिन्हें पहले

उप-मंडल अधिकारी के रूप में जाना जाता था और इसलिए,यह नहीं कहा जा सकता है कि दिया गया पट्टा 738 के बिना था।

उच्च न्यायालय ने पाया कि अपीलकर्ताओं ने भूमि नहीं खरीदी लेकिन पंजीकृत बिक्री विलेख के तहत उन्होंने जो खरीदा है वह मालवा (निर्माण का मलबा) है। उप-मंडल अधिकारी, उच्च के अनुसार न्यायालय, महांत गोविंद दास द्वारा निष्पादित बिक्री विलेख के आधार पर अपीलार्थियों के पक्ष में भूमि के हस्तांतरण का निर्देश देने वाला कोई आदेश पारित नहीं कर सकता था। G.O.150/1/185 (24)-6010, दिनांक 09-10-1987 के संदर्भ में, उप-मंडल अधिकारी/उप-कलेक्टर के पास भूमि अनुदान की मंजूरी देने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि प्राधिकरण केवल जिले के कलेक्टर के पास निहित था।

आवासीय उद्देश्य के लिए कुछ सीमा तक अनुमोदन प्रदान करना। उच्च न्यायालय ने यह भी पाया कि स्थानांतरण के लिए अपीलकर्ताओं का आवेदन यू. पी. जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार नियमों के प्रावधानों के तहत नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि किसी भी मूलभूत तथ्य का अनुरोध नहीं किया गया है।

अपीलकर्ताओं ने कहा कि उक्त प्रावधानों के तहत भूमि के आवंटन को सुरक्षित करने के लिए शर्तें मौजूद थीं। अपीलार्थियों का दावा उन श्रेणियों में से किसी के अंतर्गत नहीं आता है जिनके संबंध में उक्त नियमों

के प्रावधानों के तहत आवंटन का आदेश दिया जा सकता था। उच्च न्यायालय का विचार था कि किसी भी स्थिति में जिले के कलेक्टर को यू. पी. जमींदारी उन्मूलन और भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 122 (6) के तहत ऐसे विभाग के प्रभारी सहायक कलेक्टर द्वारा किए गए किसी भी अनियमित आवंटन को रद्द करने की शक्ति प्रदान की जाती है। उच्च न्यायालय ने महांत गोविंद दास को भूमि आवंटित करने के उप-मंडल अधिकारी के आदेश और उसके बाद अपीलार्थियों के नाम पर भूमि के हस्तांतरण का निर्देश को अमान्य और अधिकार क्षेत्र के बिना माना।

6. ये अपीलें उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ निर्देशित की जाती हैं,अपीलार्थियों की रिट याचिका को खारिज करना।

7. श्री सुधीर चंद्र, अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत कियाकि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निष्कर्ष कि उप की शक्ति भूमि के आवंटन के मामले में संभागीय अधिकारी को 9-7-1992 पर वापस ले लिया गया है जो पूरी तरह से आधारहीन है और इसकी कार्यवाही की एक प्रति पेश करने के अभाव में यह माना जाना चाहिए कि उप-मंडल अधिकारी भूमि आवंटित करने के लिए सक्षम था।

विद्वान वरिष्ठ वकील आगे प्रस्तुत किया कि कारणदर्शक नोटिस में उप-मंडल अधिकारी को प्रदत्त शक्ति को वापस लेने का कोई उल्लेख नहीं था और इस मामले को ध्यान में रखते हुए उप-मंडल अधिकारी के आदेश को

उस आधार पर दरकिनार नहीं किया जा सकता था जिसका कारणदर्शक नोटिस में उल्लेख नहीं किया गया था। विद्वान वकील के अनुसार आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।

8. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि भूमि के आवंटन से लेकर पट्टा विलेख के निष्पादन तक की कार्यवाही शुरू से ही अमान्य है। उप-मंडल अधिकारी को महांत गोविंद दास के पक्ष में सरकारी भूमि आवंटित करने और उसके बाद अपीलार्थियों के पक्ष में हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं था। उच्च न्यायालय ने ठीक ही इनकार कर दियाजिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर द्वारा पारित आदेशों में हस्तक्षेप करना।

9. हमने प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों और अभिलेख पर उपलब्ध सम्पूर्ण सामग्री पर सावधानीपूर्वक विचार किया है।

10. हमें पहले विवाद पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता नहीं है, इसका सरल कारण यह है कि अपीलकर्ताओं ने कोई मुद्दा नहीं उठाया। उनकी रिट याचिका में मामले के इस पहलू के बारे में। कारण बताओ नोटिस के अपने जवाब में, उन्होंने अनुरोध नहीं किया और यह नहीं बताया कि किस अधिकार के तहत उप-मंडल अधिकारी ने महांत गोविंद दास के पक्ष में भूमि आवंटित की और उसके बाद अपीलार्थियों के पक्ष में हस्तांतरित कर दी।

यह रिट याचिका के निपटारे के बाद ही है और इस अपील के लंबित रहने के दौरान, अपीलकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को एक पत्र संबोधित किया जिसमें उनसे भूमि के आवंटन के मामले में उप-मंडल अधिकारी की शक्तियों को वापस लेने के उनके द्वारा पारित आदेश के संबंध में जानकारी देने की आवश्यकता है। अभिलेख पर उपलब्ध सम्पूर्ण सामग्री पर विचार करने पर, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जिला कलेक्टर द्वारा जो वापस लिया गया है, वह स्पष्ट रूप से उप-मंडल अधिकारी को राज्य के राज्यपाल के लिए और उनकी ओर से पट्टा विलेख निष्पादित करने की शक्ति के संदर्भ में है। हमारे पास कानून का कोई प्रावधान नहीं लाया गया है।

नोटिस जिसके तहत उप-मंडल अधिकारी शुरू में महांत गोविंद दास को भूमि आवंटित कर सकता था और उसके बाद उसे अपीलार्थियों को हस्तांतरित कर सकता था।

11. उच्च न्यायालय ने मामले पर विस्तृत विचार करने के बाद, स्पष्ट और स्पष्ट शब्दों में पाया कि उप-मंडल अधिकारी के पास कोई अधिकार नहीं था।

सरकारी भूमि देने/आवंटित करने का अधिकार क्षेत्र उसके पास निहित है और शक्ति केवल जिला कलेक्टर के पास निहित है। अपीलकर्ताओं ने अनुरोध नहीं किया और न्यायालय की संतुष्टि के लिए यह स्थापित नहीं

किया कि उप-मंडल अधिकारी को इच्छुक पक्षों द्वारा आवेदनों के आधार पर सरकारी भूमि आवंटित/अनुदान करने का अधिकार क्षेत्र प्रदान किया गया है। यह कानून का एक मौलिक सिद्धांत है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के असाधारण अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने वाले व्यक्ति को स्वच्छ हाथों के साथ आना चाहिए और न्यायालय को तथ्यों का पूर्ण और पूर्ण खुलासा करना चाहिए। पक्षकारों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए अपने तथ्यों को चुनने का अधिकार नहीं है। न्यायालय को जांच करने में सक्षम बनाने के लिए मूलभूत तथ्यों का अनुरोध करने की आवश्यकता है।

12. इस मामले में अपीलार्थी यह स्थापित करने में विफल रहे कि उनके पास कानूनी रूप से भूमि का सुरक्षित आवंटन। यह अपीलार्थियों का कर्तव्य है कि वे अभिवचन करें और यह स्थापित करना कि उप-मंडल अधिकारी द्वारा अपने पूर्ववर्ती के पक्ष में आवंटन/अनुदान का आदेश किसी भी कानूनी अधिकार का निर्माण करता है और यह भी स्थापित करता है कि उनके पक्ष में भूमि का हस्तांतरण उनके द्वारा वैध रूप से किया गया है।

उप-मंडल अधिकारी। इस मामले को देखते हुए हमारी राय है, इस मामले में न्याय किया गया है और उच्च न्यायालय ने उप-मंडल अधिकारी

के आदेश को पुनर्जीवित करने या पुनर्जीवित करने से इनकार कर दिया है जो है कानून में अप्रवर्तनीय।

13. "सरकारी संपत्ति के प्रबंधन से संबंधित नियम", अपीलार्थियों द्वारा जो मजबूत निर्भरता रखी गई है, वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सरकारी भूमि के ऐसे किसी भी हस्तांतरण के लिए प्रावधान नहीं करती है और विचार नहीं करती है। परगनाधिकारी (उप-मंडल अधिकारी) के पास उक्त नियमों के तहत भी किसी भी व्यक्ति या व्यक्ति के पक्ष में कोई अनुदान देने का कोई अधिकार नहीं है। नियम 5, जिस पर निर्भरता रखी गई है, निम्नानुसार हैः-

> "5. सरकारी अनुदान अधिनियम के तहत पट्टे पर भूमि आवंटित की जाएगी राजस्व बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रारूप। परगनाधिकारी एतद्द्वारा महामहिम की ओर से इस पट्टा विलेख पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत राज्यपाल। इस तरह के कार्यों के लिए किसी पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।"

14. नियम के एक सादे अध्ययन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि परगनाधिकारीकेवल राज्यपाल की ओर से पट्टा विलेख पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत। नियम कहीं भी परगनाधिकारी को किसी भी व्यक्ति के

पक्ष में पट्टे पर सरकारी भूमि आवंटित करने की शक्ति प्रदान नहीं करते हैं।

15. इस मामले का एक और पहलूः उप-मंडल अधिकारी ने नहीं किया महांत गोविंद दास के पक्ष में दिए गए अनुदान को रद्द करने के बाद अपीलार्थियों के पक्ष में भूमि का आवंटन करें। पता चला कि महांत गोविंद दास अनुदान के नियमों और शर्तों का उल्लंघन करते हुए, उप-मंडल अधिकारी ने पट्टा अनुदान को रद्द कर दिया और महांत गोविंद दास पर Rs.2000/- का जुर्माना लगाया और साथ ही अपीलार्थियों के पक्ष में भूमि का हस्तांतरण किया। यह मानते हुए कि उप-मंडल अधिकारी के पास गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए भूमि का पट्टा देने का अधिकार और अधिकार क्षेत्र था, वह अपीलार्थियों के आवेदन पर गुण-दोष के आधार पर विचार कर सकता था ताकि यह तय किया जा सके कि क्या वे किसी भी सरकारी भूमि के अनुदान के हकदार हैं, लेकिन किसी भी परिस्थिति में उप-मंडल अधिकारी राजकुमार सोनी बनाम आदेश पारित नहीं कर सकते थे। अपीलार्थियों के नाम पर भूमि का हस्तांतरण

16. यह सच है कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 5.4.1999 पर जारी कारण बताएँ नोटिस में 9.7.1992 को वापस लेने के आदेश का कोई उल्लेख नहीं है। सरकारी भूमि के पट्टा अनुदान के अनुसार उप-मंडल अधिकारी को प्रदत्त शक्तियाँ। हालांकि, यह कहा गया है कि परगनाधिकारी/उप-मंडल

अधिकारी भूमि देने के लिए अधिकृत नहीं हैं, सरकारी अनुदान अधिनियम के तहत, आवासीय उद्देश्यों के लिए कुछ हद तक भूमि देने का अधिकार जिला मजिस्ट्रेट के पास निहित है। यह जिला मजिस्ट्रेट के अंतिम आदेश में उन कार्यवाहियों के बारे में उल्लेख किया गया है जिनके तहत उप-मंडल मजिस्ट्रेट की शक्तियों को उप-मंडल अधिकारी से बहुत पहले 20.5.1993 पर अनुदान के अनुसार वापस ले लिया गया था। अपीलार्थी तकनीकी रूप से यह तर्क देने में सही हो सकते हैं कि जिला कलेक्टर का आदेश उन आधारों पर आधारित है जिनका अपीलार्थी को जारी कारण दर्शाओ नोटिस में विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया था। लेकिन इसके साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि कारण बताएँ नोटिस में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि परगनाधिकारी/उप-मंडल अधिकारी नहीं हैं।

सरकारी अनुदान अधिनियम के तहत भूमि प्रदान करने के लिए अधिकृत, आवासीय उद्देश्यों के लिए कुछ हद तक भूमि प्रदान करने का अधिकार निहित है।

यदि प्राकृतिक न्याय के नियमों का कोई तकनीकी उल्लंघन हुआ था, तो यह हस्तक्षेप के लिए उपयुक्त मामला नहीं है, इस तरह के हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप एक अवैध, नहीं, शून्य आदेश का पुनरुत्थान होगा।

17. वेंकटेश्वर राव बनाम ए. पी. राज्य, आकाशवाणी (1996) एससी 828, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन पहले एक विशेष गाँव में किया गया था।

शर्तें। चूंकि वे शर्तें पूरी नहीं हुई हैं, इसलिए पंचायत समिति ने इसे दूसरे गाँव में स्थानांतरित करने का संकल्प लिया। सरकार ने अपने समीक्षा अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए पंचायत को कोई भी अवसर प्रदान किए बिना पंचायत समिति द्वारा पारित प्रस्ताव में हस्तक्षेप किया

समिति। सरकार के आदेश को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक कार्यवाही में चुनौती दी गई थी। ए. पी. उच्च न्यायालय ने कहा, आदेश पारित किया गया सरकार द्वारा समीक्षा खराब होने पर, लेकिन गुण-दोष पर हस्तक्षेप नहीं किया।

उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश की पुष्टि करते हुए कहा किः" यदि उच्च न्यायालय ने उक्त आदेश को रद्द कर दिया होता, तो उसे बहाल कर दिया जाता एक अवैध आदेश; यह एक गाँव को स्वास्थ्य केंद्र देता, पंचायत समिति द्वारा पारित वैध प्रस्तावों के विपरीत।

18. उच्चतम न्यायालय ने राय दी कि उच्च न्यायालय का इनकार करना सही थाभारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी असाधारण विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करना।

19. एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ, इस न्यायालय, पर भरोसा करते हुए वेंकटेश्वर राव (1 ऊपर) ने देखा; "उपरोक्त मामला इस प्रस्ताव के लिए स्पष्ट अधिकार है कि यह है न्यायालय के लिए हमेशा यह आवश्यक नहीं होता कि वह केवल एक आदेश को रद्द कर दे क्योंकि आदेश याचिकाकर्ता के खिलाफ उल्लंघन में पारित किया गया है डाउन के परिणामस्वरूप पहले पारित एक और आदेश की बहाली होगी याचिकाकर्ता के पक्ष में और विरोधी पक्ष के खिलाफ, का उल्लंघन करते हुए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत या अन्यथा इसके अनुसार नहीं हैं कानून।"

20. हमारे विचार में, ऊपर दिए गए स्वीकृत और निर्विवाद तथ्यों पर,जिला कलेक्टर के विवादित आदेश में किसी भी हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप अपीलार्थियों के पक्ष में पहले पारित आदेशों को बहाल किया जाएगा जो अन्यथा कानून के अनुसार नहीं हैं।

21. इन सभी कारणों से, हम अपीलों में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। द.तदनुसार अपीलें खारिज कर दी जाती हैं। हम लागत के बारे में कोई आदेश नहीं देते हैं।

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

एन. जे.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सीमा रानी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।